माइंड द गैप: लैंगिक अंतराल पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक मुद्दे) से संबंधित है।

द हिन्दू

26 दिसम्बर, 2019

"महिलाओं को संसाधनों तथा अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।"

अपने नागरिकों की उन्नति के लिए देश की प्रतिबद्धता का मूल्यांकन करने का उत्तम तरीका पुरुषों के समान महिलाओं को समान अवसर और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित कराना है। लेकिन पिछले हफ्ते जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 से यह सवाल आसानी से उठाया जा सकता है कि क्या यह सरकार देश की महिलाओं के लिए सही काम कर रही है।

इस बार भारत ने पिछली बार यानी 2018 की तुलना में चार अंकों की गिरावट दर्ज करते हुए 112वाँ स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक चार प्रमुख मापदंडों- आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तीकरण पर लिंग आधारित अंतराल की सीमा को मापता है। विशेष रूप से, यह उपलब्ध संसाधनों और अवसरों के वास्तविक स्तर के बजाय, देश में संसाधनों और अवसरों तक पहुँच में लिंग आधारित अंतराल को मापता है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वर्ष 2020 की जेंडर गैप लैंगिक असमानता (Gender Gap) रिपोर्ट में भारत को 112वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- भारत लिंग असामनता के मामले में साल 2018 के मुकाबले चार रैंक पिछड़ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की।
- आइसलैंड लैंगिक असमानता के मामले में विश्व का सबसे बेहतर देश बना हुआ है। इस देश में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है।
- डब्लूईएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्वभर में लिंगभेद कम तो हो रहा है लेकिन अभी भी महिलाओं एवं पुरुषों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यालय तथा राजनीति में भेदभाव मौजूद है।

रिपोर्ट में भारत

- डब्ल्यूईएफ ने साल 2006 में जेंडर गैप को लेकर पहली बार रिपोर्ट पेश की थी। भारत उस समय 98वें स्थान पर था।
- भारत चार मानकों में तीन पर पिछड़ गया है। भारत तब से पिछड़ते जा रहा है। भारत राजनीतिक सशक्तिकरण में 18वें स्थान पर है।
- भारत स्वास्थ्य के मामले में 150वें स्थान पर, आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में 149वें स्थान पर और शिक्षा पाने के मामले में 112वें स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बेहद सीमित हैं। यह भारत में 34.5 फीसदी, पाकिस्तान में 32.7 फीसदी, यमन में 27.3 फीसदी और इराक में 22.7 फीसदी है।
- रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व वाले देशों में भी भारत (13.8 फीसदी) काफी पीछे है।

एक छोटे से सुधार के बावजूद, भारत चार स्थान निचे आ गया है क्योंकि भारत की तुलना में कम रैंक वाले कुछ देशों ने बेहतर सुधार दिखाया है। भारत को इस बार 66.8% स्कोर प्राप्त हुआ है, साथ ही रिपोर्ट ने यह दर्शाया है कि भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर महिलाओं की स्थिति 'अनिश्चित' है। महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय आर्थिक लैंगिक अंतराल है, जहाँ इसका स्थान 153 देशों में 35.4% स्कोर के साथ 149वाँ है और पिछले संस्करण से इसे सात स्थानों का नुकसान हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भारत ने केवल एक तिहाई अंतराल को कम किया गया है।

श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी भी दुनिया में सबसे कम है और महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों की आय का केवल पाँचवां हिस्सा है। भारत की सबसे चौकाने वाली स्थिति स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के उप सूचकांक पर बनी हुई, जिसमें इसने 150वीं रैंक हासिल की है, जो जन्म के समय लिंग की पहचान या इसके प्रति उपेक्षा, हिंसा, जबरन शादी और स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव के कारण है।

इसके अलवा, इसने शैक्षिक उप सूचकांक में 112वीं रैंक हासिल की है, साथ ही इसने राजनीतिक सशक्तिकरण में 18वीं रैंक हासिल की है, जो यह दर्शाता है कि इस बार हमे किसी भी क्षेत्र में अच्छी खबर नहीं मिली है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेंडर गैप इंडेक्स भारत द्वारा आवश्यक संशोधन करने की माँग करता है। वर्तमान में सरकार जो कर रही है, वह स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है; सूचकांक में स्कोर को बेहतर बनाने के लिए सभी पहलुओं के साथ अंतरंग रूप से जुड़ने की जरूरत है और भविष्य में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।

महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उनके लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए इसे शुरू करने के प्रयासों में भारी पैमाने पर वृद्धि करनी होगी। ऐसा करने के लिए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन हो। यहाँ जो सवाल किया जा रहा है वह बुनियादी है कि क्या राज्य अपनी आधी आबादी के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से जोर दे रहा है? महिलाओं के लिए शर्तों में सुधार करने की प्रतिबद्धता किसी भी राज्य का एक गैर-परक्राम्य कर्तव्य है।

मुख्य बिंदु

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार चीन 106वें स्थान पर, श्रीलंका 102वें स्थान पर, नेपाल 101वें स्थान पर, ब्राजील 92वें स्थान पर, इंडोनेशिया 85वें स्थान पर और बांग्लादेश 50वें स्थान पर है। वहीं यमन 153वें स्थान पर, ईराक 152वें स्थान पर और पाकिस्तान 151वें स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, काम और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों में अभी भी असमानता है। हालाँकि, साल 2018 में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई थी।
- डब्ल्यूईएफ ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखा जा सकता है। राजनीतिक असमानता को खत्म होने में लगभग 95 साल लगेंगे। पिछले साल कहा जा रहा था कि इसमें लगभग 107 साल लग सकता है।

GLOBAL GENDER GAP INDEX RANKINGS 2020

Rank	Country	Score
1	Iceland	0.877
2	Norway	0.842
3	Finland	0.832
4	Sweden	0.820
5	Nicaragua	0.804
6	New Zealand	0.799
7	Ireland	0.798
8	Spain	0.795
9	Rwanda	0.791
10	Germany	0.787
21	United Kingdom	0.767
50	Bangladesh	0.726
53	United States	0.724
81	Russian Federation	0.706
92	Brazil	0.691
101	Nepal	0.680
102	Sri Lanka	0.680
106	China	0.676
112	India	0.668
121	Japan	0.652
151	Pakistan	0.564
153	Yemen	0.494

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

   1. यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा जारी की जाती है।
   2. इस रिपोर्ट में भारत को 110वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
   3. भारत ने इस रिपोर्ट में 2018 के मुकाबले 4 अंक की बढ़त हासिल की है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन असत्य हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 2 और 3

   (c) 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context the Global Gender Gap Report 2020:**

   1. This report is released by the World Economic Forum (WEF).
   2. India is ranked 110th in this report.
   3. India has gained 4 slot in this report over 2018

   Which of the above statements is/are incorrect?

   (a) 1 and 2 (b) 2 and 3

   (c) 1 and 3 (d) None of these

नोट : 25 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत में सभी क्षेत्रकों में लैंगिक असमानता का बढ़ना सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में किये जा रहे सरकारी प्रयासों की सीमा दर्शाते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

The rise of gender inequality in all sectors in India shows the limitation of government efforts being made in socio-economic sectors. Do you agree with this statement? Persent your argument in favor of your opinion. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।